अपीलीय सिविल

न्यायधीश प्रेम चंद पंडित के समक्ष

पियारी -अपीलकर्ता

बनाम

वीरन देवी - प्रतिवादी

1961 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 985

9 फ़रवरी 1972

प्रथागत कानून - झज्जर तहसील का रिवाज-ए-आम - बेटी - क्या वह अपने पिता द्वारा छोड़ी गई पैतृक संपत्ति में सफल हो सकती है - केवल संपार्श्विक - क्या बेटी को ऐसी विरासत से बाहर रखा जाए।

अभिनिर्धारित किया गया कि झज्जर तहसील के रिवाज-ए-आम के तहत, पुत्र या पुत्रों या अन्य पुरुष की विधवा, दादा या किसी भी डिग्री के संपार्श्विक के मुद्दे पर बेटियों को पैतृक संपत्ति की विरासत से बाहर रखती है, लेकिन उसके पिता द्वारा छोड़ी गई स्व-अर्जित संपत्ति से नहीं। यह निर्धारित नहीं है कि बेटियां किसी भी परिस्थिति में अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं हो सकतीं। इसके अलावा केवल संपार्श्विक ही बेटी को बाहर कर सकते हैं, लेकिन उनके वंशज प्रतिनिधित्व के अधिकार से बाहर नहीं कर सकते हैं। संपार्श्विक उत्तराधिकार के मामलों में, लिंग प्रतिनिधित्व के अधिकार में कोई बाधा नहीं है और इसलिए एक बेटी अपने पिता की उत्तराधिकारी हो सकती है। बेटियों की विरासत के अधिकार की तुलना अन्य व्यक्तियों से की जानी चाहिए, जिनके पास विरासत का अधिमान्य अधिकार है और उनकी अनुपस्थिति में बेटियां सफल होंगी। संपत्ति राज्य के पास नहीं जाएगी।

दीवान एच.जी.गुप्ता, वरिष्ठ उप न्यायाधीश, बढ़ी हुई अपीलीय शक्तियों के साथ, रोहतक ने दिनांक 21 मार्च, 1961 के आदेश से नियमित द्वितीय अपील, श्री बलवंत सिंह तेजी, उप न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, झज्जर के फैसले को पलटते हुए, दिनांक 13 जनवरी, 1961, और वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया और पार्टियों को पूरी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया।

अपीलकर्ता के वकील एस. पी. जैन।

जे. वी. गुप्ता, प्रतिवादी के वकील।

निर्णय

न्यायधीश पंडित- इस दूसरी अपील में विवाद गांव में स्थित 9 बीघा, 12 बिस्वा कृषि भूमि से संबंधित है।

धांदलान, तहसील झज्जर, जिला रोहतक। इस मुकदमे के पक्षकार गौड़ ब्राह्मण हैं। उनकी संक्षिप्त वंशावली नीचे दी गई है:-

शादी

।

। ।

नेट राम प्रीतउ = श्रीमती सुरजन (विधवा)

। ।

नरेन दत्त = श्रीमती पियारी श्रीमती वीरान

(विधवा) वादी प्रतिवादी

।

नवल

(2) यह संपत्ति प्रीतू के पास थी, जिसकी मृत्यु पर इसे उसकी विधवा सुरजन के पक्ष में कर दिया गया था। 1 अगस्त, 1954 को उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद, इसे उनकी बेटी वीरन के नाम पर बदल दिया गया। यह उत्परिवर्तन 9 जून, 1959 को प्रभावी हुआ था। मार्च, 1960 में, पियारी ने

एक घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया कि वीरन के पक्ष में इस भूमि का उत्परिवर्तन गलत तरीके से स्वीकृत किया गया था, क्योंकि कानून के तहत, वह प्रीतु की संपत्ति पर उत्तराधिकार पाने की हकदार थी क्योंकि वह नारायण दत्त की विधवा थी और प्रीतू की दूसरी डिग्री की संपार्श्विक थी। उनके द्वारा कुछ अन्य आरोप भी लगाए गए थे, लेकिन वर्तमान दूसरी अपील में हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है।

(3) वीरन ने मुकदमे का विरोध किया। उसने मुकदमा लाने के वादी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी और कहा कि वह प्रीतू की वारिस नहीं है। यह भी कहा गया कि वादी ने सूरजभान नामक व्यक्ति के साथ करेवा किया था और इस कारण उसने संपत्ति में अपना अधिकार, यदि कोई था, खो दिया था।

(4) ट्रायल न्यायाधीश ने मुकदमे का फैसला सुनाया और माना कि उत्तराधिकार के मामलों में पक्ष रीति-रिवाजों द्वारा शासित होते थे, कि मुकदमे की संपत्ति वादी के लिए पैतृक थी, कि वादी के पास मुकदमा दायर करने का अधिकार था, कि मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं था, कि वादी ने सूरजभान के साथ कोई करेवा नहीं किया था, कि मुकदमा वर्तमान स्वरूप में चलने योग्य था, कि वादी विचाराधीन संपत्ति का अधिमान्य उत्तराधिकारी था और प्रतिवादी के पक्ष में की गई भूमि का उत्परिवर्तन अवैध था।

(5) इस निर्णय से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, रोहतक के समक्ष अपील की। उनका यह भी मानना था कि उत्तराधिकार के मामलों में पार्टियाँ प्रथा द्वारा शासित होती थीं। संपत्ति का एक हिस्सा पैतृक और एक हिस्सा गैर-पैतृक माना गया। यह माना गया कि वादी के पास मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं था। यह कहा गया था कि प्रतिवादी के मुकाबले वादी संपत्ति का अधिमान्य उत्तराधिकारी नहीं था और परिणामस्वरूप, प्रतिवादी के पक्ष में भूमि का उत्परिवर्तन काफी कानूनी था। इन निष्कर्षों पर, अपील स्वीकार कर ली गई, ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को उलट दिया गया और वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया। वादी यहां दूसरी अपील लेकर आया है।

(6) अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाया गया पहला तर्क यह था कि वर्ष 1909 के झज्जर तहसील के रिवाज़-ए-आम, प्रदर्शनी पी. 3 में प्रश्न संख्या 56 के उत्तर के अनुसार, किसी भी परिस्थिति में अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर एक बेटी का अधिकार नहीं है। इस संबंध में, उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय के दो निर्णयों का उल्लेख किया- (i) माउंट जवाहरान और अन्य बनाम हजारी और अन्य[1] और (ii) माउंट मैम कौर बनाम मोलिया और अन्य[2]।

(7) प्रदर्शनी पृष्ठ 3 में प्रश्न और उत्तर उर्दू में हैं। जब अनुवाद किया जाएगा, तो वे इस प्रकार पढ़ेंगे:
"प्रश्न संख्या 56.–किस परिस्थिति में बेटियां विरासत की हकदार हैं? क्या उन्हें बेटों, या विधवा, या मृतक के निकटतम पुरुष रिश्तेदारों द्वारा बाहर रखा गया है? यदि उन्हें निकटतम पुरुष रिश्तेदार द्वारा बाहर रखा गया है, तो क्या रिश्ते की कोई निश्चित सीमा है जिसके भीतर ऐसे करीबी रिश्तेदारों को मृतक की बेटियों को बाहर करने के लिए उसके प्रति खड़ा होना होगा, यदि हां, तो सीमा का पता कैसे लगाया जाता है? यदि यह एक सामान्य पूर्वज से वंश पर निर्भर करता है, तो बताएं कि मृतक के सापेक्ष कितनी पीढ़ियों के भीतर ऐसा सामान्य पूर्वज आना चाहिए।
उत्तर- बेटियों या उनके वंशजों को विरासत में कोई संपत्ति नहीं मिलती है। पुत्र या पुत्र या विधवा या दादा के अन्य पुरुष बच्चे या किसी भी डिग्री के संपार्श्विक उन्हें बाहर रखते हैं।

(8) ऊपर दिए गए सवाल और जवाब से यह स्पष्ट हो जाएगा कि पूछा गया सवाल यह था कि क्या मृतक के बेटे, विधवा या नजदीकी पुरुष रिश्तेदार बेटी को विरासत से बाहर रखते हैं। उत्तर दिया गया कि पुत्र या पुत्र या विधवा या दादा के अन्य पुरुष बच्चे या किसी भी डिग्री के संपार्श्विक में पुत्रियों को शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि बेटियां किसी भी परिस्थिति में अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं हो सकतीं। रोहतक जिले के रिवाज-ए-आम में, जो ऊपर उल्लिखित दो निर्णयों का विषय-वस्तु था, और जिस पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने भरोसा किया था, प्रश्न संख्या 56 का उत्तर इन शर्तों में था। "गुरियानी ज़ैल के बाहर के पठानों और झज्जर के शेखों को छोड़कर सभी जनजातियों का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में बेटी या

---

[1] ए.आई.आर. 1938 लो. 562.

[2] ए.आई.आर. 1939 लो. 20.

उसके वंशजों को विरासत का अधिकार नहीं है"। वहां उत्तर, जैसा कि स्पष्ट होगा, यह था कि किसी भी परिस्थिति में बेटी या उसके वंशज को विरासत का अधिकार नहीं है। यह प्रश्न संख्या 56 था और इसका उत्तर रोहतक जिले के रिवाज-ए-आम में था, जिसकी व्याख्या माउंट जवाहरन के मामले (1) में लाहौर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने की थी और यह निर्धारित किया गया था:

"रोहतक जिले के रिवाज-ए-आम में प्रवेश के अनुसार एक बेटी को अपने पिता की ज़मीन-जायदाद, चाहे वह पैतृक हो या स्व-अर्जित, पर उत्तराधिकार पाने का कोई अधिकार नहीं है, और एक विधवा को अपने पति की संपत्ति, चाहे वह पैतृक हो या स्व-अर्जित, से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। स्वयं अर्जित. जब ऐसी प्रविष्टि को चुनौती दी जाती है तो पार्टी पर यह साबित करने का भारी बोझ होता है कि रिवाज-ए-आम में प्रवेश गलत है।

इसी तरह, माउंट मैम कौर के मामले (2) में, यह न्यायधीश स्केम्प, द्वारा देखा गया था-

"रोहतक जिले के प्रथागत कानून के अनुसार एक बेटी को विरासत पाने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए, वह उत्तराधिकारी नहीं है। इसलिए उसके पास किसी अन्य महिला द्वारा किए गए अलगाव को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है जो पूर्ण मालिक है।"

(9) इन दो फैसलों में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, रोहतक जिले के रिवाज-ए-आम से संबंधित है और उस रिवाज-ए-आम में प्रश्न संख्या 56 का उत्तर प्रश्न संख्या 56 झज्जर तहसील के रिवाज-ए-आम के उत्तर के तहत समान भाषा में नहीं दिया गया है। किसी भी स्थिति में यह देखा जाएगा कि प्रश्न क्रमांक 56 के उत्तर के अनुसार भी केवल संपार्श्विक ही पुत्री को बाहर कर सकते हैं। बेशक, इस मामले में वादी, संपार्श्विक नहीं था। वह एक संपार्श्विक नारायण दत्त की विधवा थी, या एक अन्य संपार्श्विक नवल की माँ थी। मामले के इस भाग पर, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर, यह माना जाना चाहिए कि विधवा ने अपने पति का प्रतिनिधित्व किया, जो एक संपार्श्विक था और इसलिए, "प्रश्न संख्या 56 के उत्तर के अनुसार, वह बेटी को बाहर कर देगी।"

(10) इसमें सबसे पहले, जैसा कि Al2 ने पहले ही कहा है- इसका उत्तर देने के लिए प्रयुक्त शब्द है - "संपार्श्विक"। इसलिए, उत्तर के आधार पर, तत्काल मामले में वादी, जो संपार्श्विक नहीं है,

प्रतिवादी, जो एक बेटी है, को बाहर नहीं कर सकता है। दूसरे, यदि वादी प्रतिनिधित्व के नियम पर भरोसा करना चाहती है और कहती है कि वह अपने पति का प्रतिनिधित्व करती है जो संपार्श्विक है, तो प्रतिवादी का उत्तर यह हो सकता है कि वह अपने पिता की बेटी होने के नाते, उसी प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर उसका प्रतिनिधित्व भी कर सकती है। पहले, इस बात पर कुछ विवाद था कि क्या संपार्श्विक उत्तराधिकार में, बेटी अपने पिता का प्रतिनिधित्व कर सकती है या नहीं, क्योंकि, माना जाता है कि, विधवा अपने पति का प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन इस मामले को श्रीमती कागो विधवा जय नारायण बनाम श्रीमती सी फ़ोम्बेलि[3] में इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा सुलझाया गया था। वहां यह निर्धारित किया गया कि प्रथा के तहत संपार्श्विक उत्तराधिकार के मामलों में प्रतिनिधित्व का अधिकार था, सेक्स उक्त अधिकार में कोई बाधा नहीं थी और एक बेटी अपने पिता की उत्तराधिकारी हो सकती थी। यह कहा जा सकता है कि वादी का मामला यह था कि वह नारायण दत्त की विधवा थी, जो प्रीतू की दूसरी डिग्री की संपार्श्विक थी, और इसलिए, वह प्रीतू की बेटी के मुकाबले अधिमान्य उत्तराधिकारी थी। इस मामले में ऐसा कोई उदाहरण उद्धृत या साबित नहीं किया गया है जिसमें समान परिस्थितियों में, दूसरी डिग्री संपार्श्विक की विधवा ने बेटी को विरासत से बाहर रखा हो।

(11) अपीलकर्ता के तत्कालीन विद्वान वकील द्वारा झज्जर तहसील के रिवाज-ए-आम में प्रश्न संख्या 57 का संदर्भ भी दिया गया था। अनुवादित होने पर, प्रश्न और उत्तर इस प्रकार पढ़ा जाएगा:
"प्रश्न संख्या 57- क्या बेटियों को अपने पिता की संपत्ति (1) अचल या पैतृक, (2) चल या अर्जित संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार में कोई अंतर है?
उत्तर- बेटियों को विरासत में अचल संपत्ति नहीं मिलती है। जहां तक चल संपत्ति का सवाल है, पिता या भाई जितना चाहें उतनी संपत्ति देने के हकदार हैं, भले ही उक्त संपत्ति पैतृक हो या स्वयं अर्जित की गई हो।"

(12) प्रश्न संख्या 57 के इस उत्तर के आधार पर यह तर्क दिया गया कि बेटियों को किसी भी परिस्थिति में विरासत में अचल संपत्ति नहीं मिलती है।

---

[3] एल.पी.ए. क्रमांक- 162 आई.डब्ल्यू. का निर्णय 24 नवम्बर 1970 को हुआ।

(13) इस विवाद में कोई दम नहीं है, क्योंकि इन दोनों प्रश्न संख्या 56 और 57 को उनके संबंधित उत्तरों के साथ एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। अकेले खड़े रहने पर प्रश्न संख्या 57 का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। देखा जाए तो प्रश्न संख्या 56 के उत्तर में कहा गया था कि बेटियों या उनके वंशजों को विरासत में कोई संपत्ति नहीं मिलती है। यह स्पष्ट रूप से मानता है कि विरासत बेटियों के बजाय किसी और को मिलेगी। इस उत्तर में यह कहा गया है कि दादा के पुत्र या विधवा या अन्य पुरुष पुत्र या किसी भी डिग्री की संपार्श्विक संपत्ति उन्हें बाहर कर देगी। बेटियों की तुलना में अधिमान्य उत्तराधिकारी कौन हैं, इसका पता लगाने के लिए ही प्रश्न क्रमांक 56 और उसके उत्तर पर गौर करना होगा। प्रश्न संख्या 57 के उत्तर के तहत, यह सुझाव नहीं दिया जा सकता है कि चूंकि बेटियों को अचल संपत्ति बिल्कुल भी विरासत में नहीं मिलेगी, इसलिए, उनकी अनुपस्थिति में, यह राज्य को हस्तांतरित हो जाएगी। उनके उत्तराधिकार के अधिकार की तुलना स्पष्ट रूप से अन्य व्यक्तियों के साथ की जानी चाहिए, जिनके पास विरासत का अधिमान्य अधिकार है और इसलिए, यह इस प्रकार है कि बाद की अनुपस्थिति में, बेटियां सफल होंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन सवालों और उनके जवाबों दोनों को एक साथ पढ़ना होगा। मौजूदा मामले में, प्रश्न संख्या 56 के उत्तर में उल्लिखित अधिमान्य उत्तराधिकारियों में से कोई भी वहां नहीं था, बेटी, यानी, प्रतिवादी को सफल होना था। अतः इस तर्क में कोई दम नहीं है।

(14) इसके बाद विद्वान वकील ने रैटिगन्स डाइजेस्ट ऑफ कस्टमरी लॉ के पैरा 23 का हवाला दिया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि एक बेटी केवल अपने पिता की पैतृक भूमि संपत्ति में, अपने पिता के अधिकांश पुरुष संपार्श्विक के डिफ़ॉल्ट रूप से सफल होती है और प्रस्तुत किया कि यदि वहाँ थे पिता के पुरुष संपार्श्विक के पास, तो बेटी को विरासत का कोई अधिकार नहीं होगा।

(15) इससे फिर पता चलता है कि अकेले पुरुष संपार्श्विक ही बेटी को विरासत से बाहर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, वादी पुरुष संपार्श्विक नहीं है और यदि वह अपने दावे को प्रतिनिधित्व के अधिकार पर आधारित करना चाहती है, तो उस विवाद को मेरे द्वारा पहले ही ऊपर निपटाया जा चुका है।

(16) इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रिवाज-ए-आम या सामान्य प्रथागत कानून में प्रविष्टियाँ, जैसा कि रितिगन्स डाइजेस्ट ऑफ कस्टमरी लॉ में निहित है, पैतृक संपत्ति से संबंधित है, न कि गैर-पैतृक संपत्ति से। वर्तमान मामले में, निचली अपीलीय अदालत ने पाया है कि विवादित भूमि में से केवल तीन खसरा नंबर, अर्थात् 346, 350 और 351, पैतृक साबित हुए थे। शेष संपत्ति पैतृक नहीं थी। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस निष्कर्ष पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि शेष खसरा नंबर भी पैतृक थे। विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने पाया है कि ऊपर उल्लिखित केवल तीन खसरा नंबर, पार्टियों के सामान्य पूर्वज, शादी के पास थे। जाहिर है, वे तीन खसरा नंबर पैतृक संपत्ति थे, और शेष खसरा नंबर, सामान्य पूर्वज द्वारा कब्जा नहीं किए जाने के कारण, सही ढंग से गैर-पैतृक माने गए थे। अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया गया था कि गैर-पैतृक संपत्ति की योग्यता के बावजूद, दूसरी डिग्री संपार्श्विक की विधवा बेटी को बाहर कर देगी, लेकिन इस तर्क के समर्थन में कोई निर्णय नहीं दिया गया था। वह ऐसा कोई प्राधिकार प्रस्तुत करने में भी असमर्थ रहे जिसमें कहा गया हो कि एक बेटी को अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति के संबंध में संपार्श्विक से भी बाहर रखा जाएगा।

(17) एक अन्य बिंदु है जिसका उल्लेख किया जा सकता है, अंततः, यह मामले के परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकता है। ऐसा कहा गया था कि वादी, प्यारी, अपने पति नारायण दत्त की विधवा के रूप में सफल हुई, लेकिन विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने माना कि वह नारायण दत्त की विधवा के रूप में सफल नहीं हुई, बल्कि नारायण दत्त के बेटे नवल की माँ के रूप में सफल हुई। मामले में प्रस्तुत राजस्व अंशों से, विद्वान न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि नारायण दत्त के बाद, नवल उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना और नवल की मृत्यु पर, संपत्ति पियारी के पास आ गई। निस्संदेह, वह नवल की माँ और नारायण दत्त की विधवा थीं। लेकिन चूँकि संपत्ति का अंतिम पुरुषधारक नवल था, इसलिए, विद्वान न्यायाधीश ने माना कि वह नवल की माँ के रूप में सफल हुई, न कि नारायण दत्त की विधवा के रूप में।

(18) यह तर्क अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा संभवतः इसलिए उठाया गया था क्योंकि यदि वह नवल की मां के रूप में सफल होती, न कि नारायण दत्त की विधवा के रूप में, तो वह प्रतिनिधित्व के

सिद्धांत का लाभ भी नहीं उठा सकती थी, क्योंकि ऐसे अधिकारी हैं जो नीचे बताया गया है कि एक विधवा अपने पति का प्रतिनिधित्व करती है और बेटी अपने पिता का। हालाँकि, इस प्रस्ताव के लिए कोई निर्णय नहीं है कि माँ बेटे का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन ऐसा ही हो: हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यदि वादी प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर निर्भर रहना चाहती है, तो उसे प्रतिवादी द्वारा एक दलील के साथ उचित रूप से पूरा किया जा सकता है कि उस मामले में उत्तरार्द्ध भी उसके पिता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका संपत्ति उसे विरासत में मिली है।

(19) मैंने ऊपर जो कहा है, उसके मद्देनजर यह अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है। हालाँकि, इस मामले की परिस्थितियों में, मैं पार्टियों को उनकी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

स्मृति

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
कुरूक्षेत्र, हरियाणा